SHRI K. C. PANT: I fully agree with the hop Member that meticulous care should *oe taken. But if a point ed question is asked as to the arrears •f a particul. r firm, I do not think the Government can withhold the information from Parliament.

SHRI BHUPESH GUPTA; Certainly, income-tax arrears are not private secrets, they should be known especially when public interest demands it. The point is also there that if they give any wrong answer it creates all kinds of complications and later, subsequent corrections do not remedy the situation. Thatt is why I wanted to say something—you did not allow—with regard to the Asia Foundation question. They have corrected it. Those who are in possession of the documents should have quoted letters showing that the money came without Government itself sanctioning. The result was when that lady was in Ceylon—I have seen Ceylonese papers—she was described as a CIA spy—an Indian citizen was described as a CIA spy—-because of the reply given. I do not know to what extent the recent statement is going to rectify the damage done. Suppose she is not a spy then a great damage has been done by the statement he made, to a scale which I do not understand. Therefore, he should be extremely careful in making replies, especially when they ma$_y$ have repercussions. You have made one of the Indian citizens as a spy. If she is a spy, she should be treated as such. But if she is not, then also a very serious damage has been done. Another point is. it will have the same impact . . .

SHRI K. C PANT: I am happy that he has got some soft corner for these companies.

SHRI BHUPESH GUPTA: What is the soft corner? No soft corner.

, MR. CHAIRMAN: It is all right.

SHRI BHUPESH GUPTA: I cannot allow it- He says, soft corner. But he is a company man like a director. I have not seen a share. I say, this reply should be corrected.

श्रीमती सरला भदौरिया : श्रीमन्, आपने मुझे से कहा था कि आपको इजाजत देंगे ।

MR. CHAIRMAN: I have already told you that I will not allow you to mention that thing. I allowed you last time to mention it many times. Please sit down.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) आप इसके बाद इनको इजाजत दे दें ।

MR. CHAIRMAN: I told her last time to mention the matter. Sha mentioned it.. Now, when she came to my room, I told her that no more mention should be made about it. There it ends.

श्री राजनारायण : जब सारी चीजें हो जायं, तब बाद में इनको मौका में दीजिये ।

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

I. 'RESHAM ROAD' LINKING GILGIT IN PAKISTAN OCCUPIED KASHMIR WITH SINKIANG IN CHINA

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पाक-अधिकृत काश्मीर में गिलगित को चीन में सिंकियांग से मिलाने वाली "रेशम रोड" के निर्माण की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): Mr. Chairman, Sir, the House is awave that China and Pakistan hav$_e$ been

[Shri B. R. Bhagatj

building roads to link up Pakistan-occupied Kashmir with China. The link is through the 15,000 ft. Mintaka Pass on the Sinkiang-Kashmir border. The Chinese have now completed their portion of the road north of the pass and trucks can use it during the summer months. On the Kashmir side, a fair weather jeepable road exists between Gilgit and Pasu, a distance of about 70 miles. The Pakistanis are improving this road as well as building a new jeepable road from Pasu onwards to the Mintaka Pass, a distance of another 70 miles.

On October 21, 1967, China and Pakistan signed an agreement on the opening of the Sinkiang-Gilgit link. The text of the agreement has not been published. The official Press releases issued by the two Governments announcing the agreement stated that the road provides for the reopening of the ancient overland route and would facilitate trade in the border areas as well as between China and Pakistan. According to Press reports in the Pakistan Press, the'road was due to be opened this month.

• There are two aspects of this agreement on the opening of the Sinkiang-Gilgit road to which I would like to invite the attention of the House. First, it seeks to interfere with Indian sovereignty in Kashmir. Pakistan and China have no common border, the two countries being separated by the portion of Jammu and Kashmir which is in Pakistan's illegal occupation. Thus, agreements signed by Pakistan with China concerning Pakistan-occupied Kashmir are illegal,, invalid and totally unacceptable to us. We have naturally lodged our strong protests both with the Government of China as well as Pakistan. I place on the Table of the House protest notes delivered to them against this agreement.

The second aspect of this agreement to which I should like to invite the attention of the House is that an agreement which purports to relate to flow of commerce should be kept secret. Obviously the purpose is not as innocent as it is made out to be.

The Agreement is in the line with the collusive Sino-Pak postures directed against India. I need hardly add that Government are fully aware of the threat to our security posed by this road and everything possible has been done to safeguard our defence and security.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, इस प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ बातें उपस्थित होती हैं । मंत्री महोदय ने माना है कि 15 हज़ार फीट ऊंचे दर्रे से यह सड़क आती है । मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके बाद भी मंत्री महोदय का यह कहना कि यह सड़क केवल समर के महीनों में काम में आती है और वर्ष भर काम मे नहीं आयेगी इसका क्या आधार है । (*Interruption*) 15 हज़ार फीट ऊंचाई की सड़कें इस घाटी में हैं और साल भर तक काम में आ सकती हैं, आती रही हैं, ऐसी स्थिति में क्या आपको निश्चित मालूम है कि यह सड़क वर्ष भर काम में नहीं आयेगी ।

दूसरे, जब पिछले अक्तूबर के महीने में दोनों देशों की विज्ञप्ति से इस बात का समाचार आपको मिला कि इस तरह की सड़क गिलगित को जोड़ने वाली बनाई जा रही हैं, तो आपने यह विरोधपत्र या इस सम्बन्ध में इन दोनों सरकारों से किया जाने वाला विरोध, जिसकी आपने कहा कि टेबिल आफ द हाउस पर आप कापी रख रहे हैं, यह कब किया और इस सम्बन्ध में इन दोनों सरकारों की तरफ से आपको कोई जवाब मिला या नहीं ।

तीसरे, क्या आपने इस बात की जानकारी की है कि यह सड़क, सड़क के आसपास पड़ने वाली किसी भी आबादी को नहीं जोड़ती है

और यह सड़क केवल गिलगित को जोड़ने के लिये केवलमात्र सामरिक महत्व की दृष्टि से बनाई गई है और इसका व्यापार की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। सामरिक दृष्टि से बनाई गई सड़क जो पाक अधिकृत काश्मीर के भाग में पाकिस्तान और चीन को जोड़ने के लिये बनाई जा रही है, आपने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये।

चीन ने तो 1963 में जब काश्मीर के साथ अपनी सीमा के निर्धारण की बात कही थी, तो उस समय उसका स्टेंड था कि जो आज स्थिति है उसको देखते हुए केवल उसने सीमा निर्धारण करने की कोशिश की थी, काश्मीर और चीन के बीच में। लेकिन यह सड़क निकालते समय चीन की तरफ से जो वक्तव्य आया है, उसमें गिलगित को पाकिस्तान का हिस्सा मान कर चीन और पाकिस्तान ने आपस में समझौता करने का प्रयत्न किया है। चीन के इस बदले हुये रवैया के प्रति, जिसमें उसने अब गिलगित को स्पष्ट रूप से पाकिस्तानी इलाका स्वीकार किया है आपकी तरफ से क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री बी० आर० भगत : जहां तक चीन के बदले हुये रवैये का सवाल है यह तो बात साफ है कि चीन और पाकिस्तान का जो गठबन्धन है वह भारत के खिलाफ है और यह पहले हम कह चुके हैं। इसलिये यह भी कारण है कि चीन का रवैया इस मामले के ऊपर बदला है . . .

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : आप 1963 के और आज के स्टेंड में कुछ बदल अनुभव करते हैं या नहीं।

श्री बी० आर० भगत : जहां तक लिखित बातों का सवाल है, 1963 में जिन शब्दों का वह प्रयोग करता था वह शब्द आज बदल गये हैं और माननीय सदस्य ने जो कहा वह ठीक है। हमने शुरू में भी कहा कि यह कहना कि यह बिलकुल व्यापार के लिये सड़क बनाई गई है, यह बात साफ नहीं है। माननीय सदस्य ने जो उदाहरण दिया है उससे ऐसा लगा कि यह सड़क ऐसे पास से जाती है जहां आबादी कम है। हमने अपने बयान में साफ कर दिया है कि इससे हमारी सुरक्षा को खतरा है, इससे हम आगाह हैं और जो कुछ भी हम उचित प्रबन्ध कर सकते हैं इस खतरे से बचने का, वह सब इन्तजाम हम कर रहे हैं।

इसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट नोट की बात कही। यह बात सही है कि अक्तूबर में इसकी चर्चा हुई कि दोनों के बीच में कोई समझौता हुआ है मगर चूंकि यह समझौता प्रकाशित नहीं हुआ था, हम इसकी खोज में थे कि समझौते की कापी मिले, देखें उसको कि किस तरह का समझौता है। कुछ दिनों के बाद पता चला कि यह समझौता प्रकाशित नहीं होगा, सीक्रेट रखा गया है, तब हमने अपना प्रोटेस्ट नोट उनके पास 19 अप्रैल को भेजा है। चूंकि यह सड़क खुलने वाली है, कहा जाता है कि इस महीने के अन्त में या जून में खुलेगी, इसलिये हमने अभी उनको प्रोटेस्ट नोट भेजा है।

जहां तक सड़क की बात है कि यह गर्मियों में सिर्फ चलेगी, हमारे पास जो सूचना है वह यह है कि यह सड़क, जो मिनटाका पास, सिकियांग से पास होगी, इस पर ट्रकें गर्मी के महीनों में ही चल सकती हैं। मगर माननीय सदस्य का यह कहना कि यह साल भर चालू रहेगी, इस आशंका को भी हमें ध्यान में रखना चाहिये और मैं उनसे सहमत हूं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, मैं एक और प्रश्न आपकी आज्ञा से पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पाक-अधिकृत क्षेत्र में पाकिस्तान के द्वारा इस सड़क का बनाया जाना, इस सम्बन्ध में हमने क्या दृष्टिकोण बनाया है; क्योंकि पिछले दिनों में जब मंगला बांध की बात हुई थी

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

तब जवाब देते समय यह कहा गया था कि घबराने की कोई बात नहीं, अगर इसकी वजह से पाकिस्तान उस भूमि को किसी तरह से डेवलप करता है तो जिस दिन सारा पाक-अधिकृत काश्मीर हमारे पास आयेगा उसी दिन मंगला बांध भी हमारे पास आ जायेगा और हमने मंगला बांध की सफल समाप्ति पर पाकिस्तान को बधाई भी दी थी। मेरा यह कहना है कि अब यह एक नया डेवलपमेंट का काम पाकिस्तान ने इस क्षेत्र के अन्दर करने का फैसला किया है, 19 अप्रैल को अगर उनकी तरफ से तब तक जो सारा समझौता हुआ था, उसका पता लग गया होता और हमको सरकार ने बता दिया होता, तो बधाई देने का प्रसंग चूंकि उपस्थित नहीं हुआ, इस लिये 8 महीने बाद एक प्रोटेस्ट नोट भेजने की नौबत हमारे सामने उपस्थित हुई। पाकिस्तान का जो यह रवैया है कि आज हम अपने इलाके में फरक्का बांध बना रहे हैं उस पर भी हमको वह तंग करता है और बार-बार उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लेता है और हम उसके सम्बन्ध में उससे बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे इलाके में हमसे बिना पूछे, बिना सलाह के वह सड़कें बनाता है और दुश्मन के आक्रमण की शक्ति में वृद्धि करता है तब भी हम उसके सम्बन्ध में कोई कदम उठाने के लिये तैयार नहीं हैं, तो क्या मैं यह आशा करूं कि चूंकि पाकिस्तान ने एक गलत काम हमसे बिना पूछे इस क्षेत्र में किया है पाकिस्तान के साथ फरक्का बान्ध के सम्बन्ध में होने वाली बातचीत को समाप्त किया जायगा और इसके विरोध स्वरूप कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जायगा ?

श्री बी० आर० भगत : जहां तक इस सड़क के बनाने की बात है, हमने इस बयान में भी कहा है, पहले भी कहा है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : आज ही कहा है।

श्री जे० पी० यादव : (बिहार) पहले कब कहा ?

श्री बी० आर० भगत : आप सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि जवाब क्या है।

श्री जे० पी० यादव : जवाब है क्या ?

श्री बी० आर० भगत : आप सुनने की कोशिश करिए।

जो हिस्सा पाकिस्तान के अधिकार में है वह नाजायज है वह काश्मीर का हिस्सा है और पाकिस्तान ने जबरदस्ती और नाजायज ढंग से उस पर अधिकार कर रखा है। इसलिये उन्होंने जो सड़क बनाई है तथा जो चीन से समझौता किया है, उसका हम विरोध करते हैं, उसको नहीं मानते हैं।

जहां तक इसको सुलझाने का सवाल है उसके दो ही रास्ते है या तो सारा सवाल बातचीत करके, शांतिमय तरीके से सुलझाया जाय या झगड़ा करके सुलझाएं। अभी तक हमको भरोसा है कि पाकिस्तान से बातचीत करके सुलहनामा हो सकता है और हमें करना चाहिये। दूसरा रास्ता तभी आ सकता है जब ये सब रास्ते बन्द हो जायं।

श्री जे० पी० यादव : श्रीमन . . .

MR. CHAIRMAN: Mr. Yadav, you belong to which party?

SHRI J. P. YADAV: Jan Sangh.

MR. CHAIRMAN: Your leader has already put a series of questions . . .

श्री राजनारायण : श्रीमन, इसमें लीडर और सदस्य की क्या बात है।

MR. CHAIRMAN: You can leave it to me.

श्री जे० पी० यादव : श्रीमन, मंत्री जी सही जवाब नहीं दे रहे हैं। यह देश की सार्वभौमता का सवाल है इसलिये जो ठीक

जानकार हों उनके विचार अवश्य जान लें। सरकार का कितना गलत जवाब होता है, कभी काश्मीर बोलते हैं, कभी भारत बोलते हैं, काश्मीर को अपना कहने का दम नहीं रखते हैं।

MR. CHAIRMAN: Don't tell me what I have to do. You can leave it to me. You can leave it to me as to how I should conduct the business of this House. Please do not suggest. I have some experience. *{Interruption)* Please sit down.

श्री जे० पी० यादव : सरकार की तरफ से गलत बयान होता है . . .

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Mr. Murahari.

श्री गोडे मुरहरि (उत्तर प्रदेश) : मैं यह जानना चाहूंगा कि जब गिलगित में इस तरह की रोड बन जाती है जिसके जरिये चीन के सिक्यांग को काश्मीर होकर पाकिस्तान से मिलाने की कोशिश की है और सरकार यह कहती है कि जो अकपाइड काश्मीर है वह डिस्प्यूटेड एरिया है, जो हिन्दुस्तान का भाग है और साथ ही साथ जब ताशकन्द एग्रीमेन्ट हुआ, जिसमें रूस भी शामिल है, जिसमें कई ऐसी बातें की गई हैं, जिनके जरिये हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच मेल करने की कोशिश की गई बताते हैं, तो क्या यह सरकार उचित नहीं समझती कि इस बारे में रूस का ध्यान भी दिलाये और ताशकन्द एग्रीमेन्ट के बारे में एक बार फिर चर्चा कर ले? साथ साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह जरूरी नहीं होगा कि जो यह रोड बनी है, जो अक्साईचिन में रोड चीन बना रहा है, उससे हिन्दुस्तान की रक्षा का जो मामला है उसमें बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा, वह सिर्फ ट्रेड के लिये इस्तेमाल नहीं होगा, इसका इस्तेमाल होगा मिलिटरी के लिये भी? इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार यह बताये साथ कि इसको नजर में रखते हुए डिफेंस को ठीक करने के लिये सरकार क्या करने वाली है?

श्री बी० आर० भगत : माननीय सदस्य ने जो कहा कि यह हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाला है, यह बात बिलकुल सही है। मैंने भी यह कहा है। जहां तक रूस को मालूम होने की बात है, उनको मालूम है, हमने बताया भी है कि पाकिस्तान और चीन की साजिश चल रही है, ये पोस्चर्स हमारे खिलाफ हो रहे हैं और यह पोस्चर भी हिन्दुस्तान के खिलाफ है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा को जो खतरा उत्पन्न हो गया है, उससे सावधान रहने और मुकाबला करने की हम सब तैयारी कर रहे हैं।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं चाहूंगा आप उसको ध्यान से सुनें।

श्री जे० पी० यादव : श्रीमन्, आपकी व्यवस्था के मुताबिक मैं खड़ा हुआ हूं। आपने पूछा था कि किस संस्था के हो, उस हिसाब से भी मेरी बारी आती है।

श्री राजनारायण : आप ही बोलें, मैं बाद में कहूंगा।

श्री जे० पी० यादव : हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajnarain rose before you and I noted down his name; thefore, there is no question of your demanding that I should cau you first. I shall try to see that the opinion of the whole House is before the Government. I would like all sections of the House to have their say, especially the various parties. And regarding Members also, I shall decide who should be called first and who should be called last. Please sit down. Mr. Yadav, Mr. Niranjan Varma

[Mr. Chairman] belongs to Jan Sangh. You belong to Jan Sangh. Supposing I call every Jan Sangh Member and do not call others, that would not be proper. Therefore, in this matter you better leave it to me. Trust me to discharge my duties in a proper manner. I will be most impartial to everyone. I am trying to see that every party is able to represent its views. Therefore, do not go too far and insist "I must speak, I must speak." Please don't dictate to me. Yes, Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारी आपसे कर बद्ध प्रार्थना है कि सम्मानित सदस्य को आप जरूर मौका दें, उनके पास काफी मैटर है । श्रीमन्, हमारा छोटा सा सवाल है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि 21 अक्टूबर को गत वर्ष समझौता हुआ, मगर उसका ब्यौरा नहीं आया, इसलिये भारत की सरकार ने कुछ लिखा नहीं । 181 दिन बीत गये, 181 दिन बीतने के बाद इस सरकार के दिमाग में यह बात आई कि सरकार को कुछ लिखना चाहिये जबकि वहां सड़क बन गई । मैं जानना चाहता हूं कि जब 21 अक्टूबर के समझौते की चर्चा अखबारों में आई तो सरकार की खुफिया, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स रही होगी और जब वहां सड़क बननी शुरू हुई, समझौते की डीटेल न भी आई, लेकिन जब समझौते के तदनुकूल काम शुरू हो गया, तो भारत की सरकार ने उस काम को, जिसे वह बिलकुल इल्लीगल, गलत समझती थी उसको रोकने के लिये क्या तदबीर की ? यह मेरा सिम्पल प्रश्न है ।

श्री बी० आर० भगत : उन्होंने कहा कि 181 दिन बीत गये और पता नहीं लगा । मैंने बताया कि हमने कोशिश की । मामूली समझौता होता तो पता लग सकता था । इसको प्रकाशित नहीं किया गया, इसको गुप्त रखा गया । जो चीज गुप्त रखी गई हो उसका पता लगाना मुश्किल है ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री बी० आर० भगत : सुन लीजिये ।

श्री राजनारायण : पाइन्ट आफ आर्डर है । मैं चाहूंगा कि सरकार हमारे सवाल के जवाब में रिगमरोल न करे । हमने सवाल किया है कि समझौता प्रकाशित न हुआ हो मगर जब समझौते का काम सशरीर, साक्षात होने लगा, तो जब समझौते का काम होने लगा, जो गैर-कानूनी काम था, तो सरकार ने उसको रोकने की क्या कोशिश की ?

श्री बी० आर० भगत : जो चीन अपने इलाके में बना रहा है, सिक्यांग में उसे रोकने का सवाल नहीं है । जहां तक पाकिस्तान बना रहा है काश्मीर के उस हिस्से में जिसको उसने नाजायज कब्जे में रखा हुआ है, उसके बारे में हमने शुरू से कहा है कि हम विरोध करते हैं । पहले भी सवाल उठा था सदन में उस समय जवाब दिया गया था और हमारी ओर से कहा गया था कि इस प्रकार का काम पाकिस्तान कर रहा है, यह बिलकुल हमारी सुरक्षा का खतरा है, ये सारी बातें पहले भी बताई गई थीं ।

जहां तक रोकने का सवाल है, पाकिस्तान यह नाजायज ढंग से कर रहा है, यह हमने सब जगह बताया है । कोई सामरिक कार्यवाही करके रोका जाय, उसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है ।

B. CHAIRMAN: Mr. Yadav. Now, you have no right to demand that you must be allowed to put questions about this matter. But I am now asking you, independently of your views in the matter, to ask for clarifications as briefly as possible.

श्री जे० पी० यादव : श्रीमन् कोई भी चीज बिना आपकी अनुमति से बोलने की बात नहीं होगी, लेकिन आपसे अनुमती के लिये कहने का अधिकार हमें रहेगा ।

MR. CHAIRMAN: No, no, I do not say that. Your name is not here. Mr. Bhandari's name alone is her« and I

am trying to give as much opportunity as possible. Therefore, do not be angry if I do not call you. (Interruption) You can consult your leader in this matter because you are new; he will know better.

श्री जे० पी० यादव : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार और पाकिस्तान के बीच जब काश्मीर सम्बन्धी बातें उठती हैं तो सरकार के पास 370 दफा का क्या जवाब है जिसमें काश्मीर को आपका पूर्णतः अंग नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक अंग कहने के लिए एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान की आवश्यकता होती है लेकिन काश्मीर के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है। अभी भी आप राष्ट्रपति को काश्मीर में जमीन नहीं लेने दी जा सकती, ऐसी स्थिति नहीं है कि आप उसे अपना कह सकें। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार को यह गलत भ्रम भी हो जाता है कि कोई दुश्मन देश अपने देश में ऐसी सड़क बनाता हो जो हमारे देश पर आक्रमण करने का रास्ता बन सकती है तो हमारा काम है कि उसके मुताबिक कदम उठायें। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास प्रोटेस्ट, स्ट्रांग प्रोटेस्ट और एम्फेटिक प्रोटेस्ट के अलावा कौन सा ऐसा जरिया है जिससे वह पाकिस्तान को समझा सके ?

श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश) : आप बताइए ।

श्री जे० पी० यादव : हम बता देंगे, हम बता भी रहे हैं। हमने उस काश्मीर को बचाने के लिए जनसंघ के संस्थापक का बलिदान दिया है जिससे शेख अब्दुल्ला एक्सपोज हुआ। उसे बचाने के लिये हम लड़ रहे हैं और काश्मीर को हम किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रेसिडेन्ट को जमीन लेने की दिक्कत हुई तो आप एक सेन्ट्रल एक्ट इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं लेकिन 370 दफा खत्म कर आप काश्मीर अपना नहीं कह सके हैं। तीसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि गिलगित तो दुनिया का सब से बड़ा सामरिक स्थल है, तो उस गिलगित का फैसला करने के लिये या जो आकूपाइड काश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है उसको लेने के लिए क्या और कौन सा प्रयास आपने किया है और आगे करने वाले हैं सिवाय लिखा-पढ़ी के, इसको छोड़कर और कुछ क्या करने वाले हैं ।

श्री बी० आर० भगत : जहां तक काश्मीर का और हमारा आन्तरिक संबंध है जिसके लिये संविधान की धारा का उन्होंने उदाहरण दिया वह तो एक अलग बात है और उस पर एक अलग बहस हो सकती है। जहां तक इसका सवाल है कि हमने क्या किया गिलगित को लेने का या उस सब को करने का जो कि उन्होंने कहा तो यह तो मैंने बताया कि तरीके दो होते हैं, एक शांतिमय तरीका कि बात करके हल करना, दुनिया का एक फोरम है और अपने मित्र देश हैं उन सब में एक तरह से इसको सुलझाना, जिसको हम कर रहे हैं और दूसरा तरीका होता है फोर्स का, शक्ति का तरीका, तो माननीय सदस्य अगर यह चाहते हैं कि चूंकि कुछ नहीं हो रहा है तो शक्ति का प्रयोग किया जाय, वह तो अलग बात है, उसको हम अभी जायज नहीं समझते, मगर उसके अलावा और जितनी बातें हम कर रहे हैं वह बताया . . .

श्री जे० पी० यादव : क्या कर रहे हैं, नोट भेजते हैं ।

श्री बी० आर० भगत : हमने यह बिल्कुल घोषणा कर दी कि काश्मीर हमारा एक अंग है, पाकिस्तान ने इसका नाजायज कब्जा किया है, हर तरह से, हर उपाय से यह हमको वापस आना चाहिये ।

श्री जे० पी० यादव : यह प्रथा छोड़िये, यह क्या बात है ।

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : श्रीमान वह बताने का कष्ट करें . . .

شری سید حسین (جموں اور کشمیر) : چیرمین صاحب - میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں - آپ مجھے اس کے لئے موقعہ دیں -

†[श्री सैयद हुसैन (जम्मू और काश्मीर) : चेयरमैन साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । आप मुझे इसके लिए मौका दें ।]

MR. CHAIRMAN: I will give you an opportunity after him. He stood up long before you got up.

श्री निरंजन वर्मा : श्रीमान को क्या यह मालूम है कि गिलगित प्रान्त बहुत पहले से ही समर-भूमि रहा है, अंग्रेजों के समय में जब गिलगित था तब उस समय वहां पर पांच राष्ट्रों की सीमा मिलती थी और इसके बाद जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें भी उस स्थान पर अधिक लक्ष्य दिया और संसार में छोटे छोटे राष्ट्र नहीं बल्कि सबल राष्ट्र भी गुटबन्दी करते हैं, जैसे कि नाटो, सिएटो आदि में हैं, और अभी आपने यह उत्तर दिया कि रूस को हमने यह जानकारी दे दी है, तो क्या यह सम्भव नहीं है कि जब चीन में और रूस में सिकियांग के ऊपर और दूसरे मामलों के ऊपर कुछ कलह है और अफ्रीदियों के मामले में और इसी तरह से पख्तूनों के मामले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपस में कुछ संघर्ष है, तो अफगानिस्तान और रूस के साथ बैठकर इस मामले पर विचार करें और अगर श्रीमान का ऐसा विचार है कि ऐसा हो सकता है तो इस दिशा में आपने कोई कार्यवाही की या नहीं की ।

श्री बी० आर० भगत : अब यह तो सवाल है कि अफगानिस्तान से पख्तूनिस्तान के आधार पर मिल कर कोई रास्ता निकालें, यह तो इस सवाल का समय नहीं है ।

†[ ] Hindi Translitration.

श्री निरंजन वर्मा : यह मेरा मतलब नहीं है ।

श्री बी० आर० भगत : आपने सवाल तो यही किया है ।

شری سید حسین : چیرمین صاحب میں آپ کی وساطت سے جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار یہ بتائے کہ جب حال ہی میں لندن رپورٹر نے یہ خبر دی تھی کہ چوری چھپے کوئی ایک سازش ہو رہی ہے گوریلاز کو بھیجنے کی اور جب کہ کل ہی "ٹائمز آف انڈیا" میں پھر خبر آئی ہے کہ ماؤزی تنگ کے تیار کردہ ایجنٹ وہاں آئے ہیں ادھر سے لوٹ آئے ہیں جو کہ اکوپائڈ تنگ کشمیر میں اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ کرینگے اور وہاں وہ گوریلا حملہ کی تیاری کر رہے ہیں - یہ کل کے "ٹائمز آف انڈیا" میں خبر آئی ہے - تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ شیخ عبداللہ جب یہاں سے واپس گئے اور کشمیر ایر پورٹ میں انہوں نے کہا کیونکہ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس میں کیا راز ہے کہ اس طریقہ سے کوئی گوریلا تیاری کی جا رہی ہے - کیا ایسی کوئی چیز ہے جو کہ چوری چھپے کی جائے تو وہ بولے دنیا کو بتایا جائے - میں سمجھتا ہوں کہ شیخ عبداللہ بلف کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو غافل نہیں ہونا چاہئے - جب انہوں نے پہلی دفعہ وہاں چو - این - لائی سے

مل کو حج کے بہانہ سے ساری سازش میں شرکت کرکے کام کیا جب کہ پاکستان نے پرانا حملہ کیا کشمیر پر ہندوستان پر تو پھر کیا آج ہماری سرکار ایپیکیبل کی پالیسی پر اور اپیزمینٹ کی پالیسی چلائے گی یا وہ ویجیلینٹ ہے کہ اور دوسرا اٹیک ہمارے انڈیا پر ہمارے کشمیر پر نہیں ہو - میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سرکار اس قدر ویجیلینٹ ہے اور کیا پری کاشنری میژرس وہ لے رہی ہے ?

†[श्री **सैयद हुसैन** (जम्मू और काश्मीर) : चेयरमैन साहब, मैं आपकी वसातत से यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह बताये कि जब हाल में लन्दन रिपोर्टर ने यह खबर दी थी कि चोरी छिपे कोई एक साजिश हो रही है, गुरीलाज को भेजने की, और जबकि कल ही टाइम्स आफ इंडिया में फिर खबर आई है कि माओ त्से तंग के तैयार-करदा एजेंट वहां आये हैं, उधर से लौट आये हैं, जो कि अक्यूपाइड काश्मीर में स्टूडेंट्स को ट्रेंड करेंगे, और वहां वह गुरीला हमले की तैयारी कर रहे हैं—यह कल के टाइम्स आफ इंडिया में खबर आई है—तो मैं जानना चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला जब यहां से वापस गये और काश्मीर एयर पोर्ट में उन्होंने कहा, क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि इसमें क्या राज है कि इस तरीके से कोई गुरीला तैयारी की जा रही है क्या ऐसी कोई चीज है जो कि चोरी छिपे की जाये, तो वो बोले, दुनिया को बताया जाये। मैं समझता हूं कि शेख अब्दुल्ला ब्लफ करना चाहते हैं और हमको गाफिल नहीं होना चाहिये। जब उन्होंने पहली दफा वहां चू एन लाई से मिलकर हज के बहाने से साजिश में शरकत करके काम किया, जबकि पाकिस्तान ने पुराना हमला किया कश्मीर पर, हिन्दुस्तान पर, तो फिर क्या आज हमारी सरकार एमीकेबल की पालिसी और अपीजमेन्ट की पालिसी चलायेगी या वह विजिलेंट है कि और दूसरा अटेक हमारे इंडिया पर, काश्मीर पर, नहीं हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बिजिलेंट हैं और क्या सरकार प्रिकाशनरी मेजर्स ले रही है।]

श्री बी० आर० भगत : ये सारे सवाल इस पर नहीं उठते लेकिन जहां तक अपीजमेंट की पालिसी की बात है, कि हम अपीजमेंट की पालिसी चलायेंगे तो यह बिल्कुल गलत है और वह हम नहीं चलायेंगे। जहां तक यह कि शेख अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं उससे आगाह हैं या यह कि गुरिल्ला का काम वहां शुरु हुआ है तो उससे, उन बातों से हम बिल्कुल आगाह हैं। हम यह माननीय सदस्य को बता देना चाहते हैं।

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): May I know frcm the hon. Minister whether he is in a position to inform this House as to whether there are any other instances of collusion between Pakistan and China which involves the use of the Pakistan-held Kashmir, because there was a discussion long time ago between Pakistan and China with regard to preparing certain plans involving the use of Pakistan-held territory of Kashmir to direct military offensives against India?

SHRI B. R. BHAGAT: There is no dearth of instances of collusion between Pakistan and China. One example is the Border Agreement that Pakistan signed with China under which it gave away parts of Kashmir territory to China. This road is another example. Then a large quan-tam of military armour has been given to Pakistan by China. These are some of the very glaring instances of their postures against India. Then you know what the Peking Radio is saying and what Pakistan is saying about this country. There are a number of instances which veuy

t [ ] Hindi transliteration.